



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935

No. 48]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2014

सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास में मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी

कोरम:

(i) श्री टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2014 के 10वें दिन पारित)

यह मामला, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करने से संबंधित है।

2. सीएचपीटी का मौजूदा दरमान (सीओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी दिनांक 10 नवम्बर, 2010, जिसे 11 जनवरी, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण सीएचपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता पिछली बार अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक विस्तारित की थी।

3. सीएचपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 19 फरवरी, 2013 और 29 मई, 2013 द्वारा अपना प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श के लिए लिया गया है। हमारे पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा इसके प्रस्ताव पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। इस मामले पर संयुक्त सुनवाई 27 सितम्बर, 2013

को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, सीएचपीटी से संयुक्त सुनवाई में निर्णीत बिन्दुओं पर कार्रवाई शुरू करने और हमारे पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर प्रत्युत्तर भेजने का अनुरोध भी किया गया था। सीएचपीटी के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। जब सीएचपीटी का प्रत्युत्तर प्राप्त होगा तक इसकी आगे जाँच की जाएगी और इसमें समय लगेगा। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, इस मामले पर विचार करने में प्राधिकरण को कुछ और समय लगेगा।

4. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस दिनांक 20 दिसम्बर, 2013, जिसे जी. सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता को विस्तारित किया है।

5. सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो चुकी है। पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में यथा दी गई मामले की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए और अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए इस मामले हेतु अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए और यह भी स्वीकार करते हुए कि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बार प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2014

No. TAMP/45/2008-CHPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/45/2008-CHPT

QUORUM:

- (i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 10th day of January 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/45/2008-CHPT, dated 10 November, 2010 which is notified in the Gazette of India on 11 January, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of CHPT twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of CHPT till 31 December, 2013 *vide* its Order dated 29 October, 2013.

3. The proposal filed by the CHPT *vide* its letter dated 19 February, 2013 and 29 May, 2013 is registered as tariff case and taken on consultation with the concerned users/user association. The additional information/clarification sought on its proposal *vide* our letter dated 24 September, 2013 is awaited. Joint hearing on the case was held on 27 September, 2013. As agreed at the joint hearing, the CHPT was requested to initiate action on the points decided at the joint hearing and also furnish its response to our queries raised *vide* our letter dated 24 September, 2013. The response of the CHPT is awaited. Response of the CHPT when received will have to be further examined which will involve time. In view of the above position, it will take some time for the case to mature for consideration of this Authority.

4. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March, 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 *vide* its Order No. TAMP/21/2009-WS, dated 20 December 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December, 2013 *vide* G. No. 340.

5. The extended validity of the existing SOR of CHPT expired on 31 December, 2013. Considering the present status of the case as brought out in the preceding paragraphs and recognizing that the time required for this case to mature for consideration and also recognising that as the validity of the Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March, 2014 this Authority extends the validity of the existing SOR till 31 March, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/13]